



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2016/ज्येष्ठ 11, 1938

No. 169]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2016/ JYAISTHA 11, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली 1 जून, 2016

विषय : “दोनों रूपों में नेप्थलीन”- चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, रूस, ईरान, जापान के मूल की या वहां से निर्यातित अपरिष्कृत नेप्थलीन और चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित परिष्कृत नेप्थलीन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

सं. 14/35/2015-डीजीएडी.—मै. हिमाद्रि कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष अपरिष्कृत और परिष्कृत नेप्थलीन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अपरिष्कृत नेप्थलीन के आयातों में शामिल देश चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, रूस, ईरान, जापान हैं जबकि परिष्कृत नेप्थलीन के आयातों में शामिल देश चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और ताइवान है। ऊपर उल्लिखित देशों को आगे संबद्ध देश भी कहा गया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया

जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने पर विचार किया जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह आवेदन मै. हिमाद्रि कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. द्वारा दायर किया गया है और मै. सुप्रीमो पेट्रो सिंथ स्पेशियलटीज और मै. इंडियन पेट्रो-कोल प्रोडक्ट्स, जो अपरिष्कृत नेपथलीन और परिष्कृत नेपथलीन के उत्पादक हैं, द्वारा उसका समर्थित है। भारत में अपरिष्कृत नेपथलीन के ऐसे अन्य उत्पादक भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारों इस्पात संयंत्र, विजाग इस्पात संयंत्र, अपर्णा कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड और सुप्रीम इंडस्ट्रीज हैं। परिष्कृत नेपथलीन का उत्पादन करने वाले अन्य उत्पादक सुप्रीम इंडस्ट्रीज और जया हाउसहोल्ड प्रॉडक्ट्स हैं।

4. याचिकाकर्ता ने बताया है कि उन्होंने केवल डाउनस्ट्रीम उत्पाद आवद्ध खपत हेतु और न कि प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री के लिए जॉच अवधि में चीन और रूस से अपरिष्कृत नेपथलीन का आयात किया है। उन्होंने यह भी घोषण की है कि तथापि वे संबद्ध देश में पीयूसी कि किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।

5. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व में आवेदक द्वारा किए गए आयातों के संबंध में मात्रा, प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर संबद्ध वस्तु का आयात करने वाले एक आवेदक उत्पादक पर उचित ढंग से विचार किया है। इस मामले में भी, इन पहलुओं के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि समर्थक घरेलू उत्पादकों के साथ याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

6. वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद 'दोनों रूपों में नेपथलीन अर्थात् अपरिष्कृत नेपथलीन और परिष्कृत नेपथलीन' है।

7. अपरिष्कृत नेपथलीन एक क्रिस्टलीय, गंधयुक्त, सफेद पाउडर कार्बनिक यौगिक होता है। इसे कोल तार के डिस्टिलेशन से उत्पादित किया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न रसायनों, रंजकों और मध्यवर्ती वस्तुओं, प्लास्टिसाइजर्स और सीमेंट कंक्रीट में रीइनफोर्सिंग एजेंट के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में होता है। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, नेपथलीन का अर्थ अपरिष्कृत नेपथलीन है।

8. परिष्कृत नेपथलीन या शुद्ध नेपथलीन को अपरिष्कृत नेपथलीन से अशुद्धियां निकालकर उत्पादित किया जाता है। परिष्कृत नेपथलीन का प्रयोग रंजकों और मध्यवर्ती वस्तुओं, चमड़ा रसायनों, नेपथलीन मोथ गोलियों और भेषजों के उत्पादन में किया जाता है।

9. अपरिष्कृत नेपथलीन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 2707 40 00 के अधीन अध्याय 27 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। परिष्कृत नेपथलीन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 2902 90 40 के अधीन अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

10. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नेपथलीन (अपरिष्कृत और परिष्कृत) और संबद्ध देशों से आयातित नेपथलीन भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

शामिल देश

11. वर्तमान जांच चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, रूस, ईरान, जापान से अपरिष्कृत नेपथलीन और चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और ताइवान (जिन्हें 'संबद्ध देश' भी कहा गया है) से परिष्कृत नेपथलीन के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य**चीन**

12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के संबंध में नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अधीन कार्य कर रहे हैं। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण. में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

यूरोपीय संघ, रूस, ईरान, जापान और ताइवान

13. आवेदक ने यूरोपीय संघ, रूस, ईरान, जापान और ताइवान में सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग के खपत संबंधी मानकों और कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करते हुए इन संबद्ध देशों में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर निर्धारित करने का दावा किया है। विद्युत की लागत संबंधित संबद्ध देशों में विद्युत की दरों पर आधारित हैं। नेपथलीन के दो रूपों में लागत और कीमत में भारी अंतर होने के कारण याचिकाकर्ता ने अपरिष्कृत और परिष्कृत नेपथलीन के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य निर्धारित करने का दावा किया है।

निर्यात कीमत

14. आवेदकों द्वारा कारखाना-द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण एक गौण स्रोत आईबीआईएस से प्राप्त सौदा-वार आंकड़ों के आधार पर किया गया है और समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े, बैंक प्रभार, कमीशन, और वैट समायोजनों (केवल चीन के मामले में) के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं और समायोजनों का आधार उपलब्ध कराए हैं।

पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत की तुलना अपरिष्कृत और परिष्कृत नेपथलीन के लिए अलग-अलग की गई है जो दर्शाता है कि संबद्ध देशों द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

16. याचिकाकर्ताओं ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की बड़ी हुई मात्रा, कीमत ह्रास, कम कीमत पर बिक्री, घरेलू उद्योग के लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद प्रवाह के अनुसार परिणामी प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

जांच अवधि (पीओआई)

17. वर्तमान जाँच के लिए जांच अवधि 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 (12 महीनों) की है। तथापि, जाँच अवधि में अप्रैल 11 से मार्च 12, अप्रैल 2012- मार्च 2013, अप्रैल 2013- मार्च 2014, अप्रैल 2014- मार्च 2015 और जांच अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय****वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग****चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,****नई दिल्ली- 110001**

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

20. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

23. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

24. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

27. सार्वक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2016

Subject: Anti Dumping investigation concerning imports of “Naphthalene in both its forms”. – Crude Naphthalene originating in or exported from China PR, European Union, Russia, Iran, and Japan and Refined Naphthalene originating in or exported from China PR, European Union and Taiwan.

No.14/35/2015-DGAD.—M/s. Himadri Chemicals & Industries Ltd. (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty concerning imports of Crude and Refined Naphthalene (also referred to as Subject goods). The Countries concerning Crude Naphthalene imports are China PR, European Union, Russia, Iran and Japan, while the Countries concerning Refined Naphthalene imports are China PR, European Union and Taiwan. The above mentioned countries herein after are also referred to as the Subject Countries.

2. And whereas, the Authority notes that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and ‘injury’ exists justifying initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to consider recommending an amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The Application has been filed by M/s Himadri Chemicals & Industries Ltd. and supported by M/s Supreme Petro Synth Specialities and M/s Indian Petro-Coal Products both being producers of Crude and Refined Naphthalene. The other producers of Crude Naphthalene in India are Bhilai Steel Plant, Bokaro Steel Plant, Vizag Steel Plant, Aparna Carbons Private Limited and Supreme Industries. The other producers of Refined Naphthalene are Supreme Industries and Jaya Household Products.

4. The petitioner has submitted that they have imported Crude Naphthalene from China and Russia in the POI only for purpose of captive consumption for a downstream product and not for direct commercial sales. They have further declared that they are not related either to any exporter or producer in the subject country or any importer of the in India of the PUC.

5. The Authority notes that in past, eligibility of an applicant producer who imported the subject goods has been appropriately considered based on the quantum, nature and circumstances regarding imports made by the applicant. In this case also, keeping in view these aspects, the Authority holds that the petitioner along with supporting domestic producers constitutes an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and satisfies the criteria of standing also in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

6. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Naphthalene in both its forms i.e. Crude and Refined.

7. Crude Naphthalene is a crystalline, aromatic, white powder organic compound. It is produced by distillation of coal-tar and is used as a raw material for manufacturing various chemicals, Dyes and intermediates, plasticizers and reinforcing agent in cement concrete. Unless specified Naphthalene means Crude Naphthalene.

8. Refined or-pure Naphthalene is produced from crude Naphthalene by removing impurities. Refined Naphthalene is used for producing dyes and intermediates, leather chemicals, Naphthalene mouth balls and pharmaceuticals.

9. Crude Naphthalene is classified under Chapter 27 under sub heading 2707 40 00 of Customs Tariff Act, 1975. Refined Naphthalene is classified under Chapter 29 under sub heading 2902 90 40 of Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is however indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

Like Article

10. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Naphthalene (Crude and Refined) produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the domestic industry in India as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

Countries involved

11. The present investigation is in respect of alleged dumping of Crude Naphthalene from China PR, European Union, Russia, Iran and, Japan and Refined Naphthalene from China PR, European Union and Taiwan. (referred to as the “subject countries”).

Normal Value

China

12. Applicant has claimed that China should be treated as a non-market economy and normal value in case of China should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

European Union, Russia, Iran, Japan and Taiwan

13. The applicant has claimed determination of normal value in European Union, Russia, Iran, Japan and Taiwan on the basis of best estimates of cost of production in these subject countries, considering consumption norms of the domestic industry and international prices of raw materials. The power cost is based on the power rates in the respective subject countries. Due to significant cost and price difference in the two forms of Naphthalene, the petitioner has claimed determination of separate normal value for crude and refined naphthalene.

Export Price

14. The applicant has determined ex-factory export price on the basis of transaction wise data procured from IBIS a secondary source and providing evidence and basis of adjustments on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, bank charges, commission and VAT adjustment (in case of China only).

Dumping Margin

15. The comparison of normal values with the ex-factory export price has been carried out separately for crude and refined Naphthalene which shows a considerable dumping margin in respect of the subject goods exported by the subject countries.

Injury and Causal Link

16. The petitioner has furnished evidence regarding injury due to alleged dumping due to increased imports in absolute terms and relative to production and consumption in India, price depression, price underselling and adverse impact on profitability, return on capital employed, and cash flow of the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by alleged dumped imports from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation (POI)

17. The period of investigation for the present investigation is from 1st January, 2015 to 31st December 2015 (12 months). The injury investigation period will however cover the periods Apr'11-Mar'12, Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14, Apr'14-Mar'15 and the period of investigation.

Submission of information

18. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

20. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

22. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

23. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

24. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance

of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

28. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A.K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority